

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

30.09.2018 की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अधीन मानीटरिंग और रिपोर्ट

September, 2018 माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन: 121 और प्राप्त राशि:रु. 90/-

[illegible]

[illegible]

करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं																
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विकास, सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्य विधान अथवा सामान्य विधि अथवा अन्य किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो																

**** विभाग की वेबसाइट <http://darpg-grievance.nic.in> में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है ।**